

प्रेषक,

डा० अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषय:-

दैवीय आपदा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 1472/VII-2-13/204-उद्योग/2001 दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रदेश में खादी वस्त्रों के प्रोत्साहन हेतु राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में उत्पादन तथा बिक्री से संलग्न पंजीकृत संस्थाओं को खादी वस्त्रों की स्वयं के उत्पादन की बिक्री पर रिबेट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से 108 कार्यकारी दिवसों के लिए 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। शासनादेश दिनांक 27.09.2013 के क्रम में प्रदेश में दैवीय आपदा से हुयी क्षति के दृष्टिगत केवल चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रांतीय रिबेट 02 अक्टूबर, 2013 से ही 108 कार्यकारी दिवसों के लिये निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा निर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- (ii) संस्थाओं द्वारा रिबेट दावों के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत उत्पादन/बिक्री का वार्षिक लक्ष्यांक का प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iii) रिबेट दावों के साथ संगत अवधि का बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) इंगित अवधि का प्रारम्भ से अंत तक कच्चे माल तथा उत्पादित माल की स्टॉक सूची का विवरण संलग्न किया जाना होगा।
- (v) इंगित अवधि में बैंक से आहरण एवं जमा की गयी धनराशि को क्रमशः व्यय एवं स्रोत का विवरण तिथिवार संगत साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) रिबेट दावों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इंगित रैंडम मामलों की जांच निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा:-
 - 1-जिला प्रशासन के प्रतिनिधि (उप जिलाधिकारी)।
 - 2-महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
 - 3-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
- (vii) गठित समिति द्वारा रिबेट अवधि में एक बार संस्थाओं के रसीद बुक, स्टॉक बुक, बैंक स्टेटमेंट एवं वास्तविक उपलब्ध कच्चा माल, तैयार माल का भी संज्ञान लिया जायेगा।
- (viii) कतिपय रैंडम आधार पर चयनित दावों का परीक्षण अपर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर पर भी किया जायेगा।

- (ix) संस्थाओं के रिबेट दावों के सापेक्ष उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत उत्पादित सामान की आपूर्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2926/VII-II-08/204-उद्योग/01 दिनांक 3.11.2008 के निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।
- (x) संस्था को बैंक/खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित होने का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (xi) संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के0वी0आई0सी0) से विपणन विकास सहायता (एम0डी0ए0) में जितनी सहायता प्राप्त हुई है, उसी आधार पर उत्पादन की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा।
2. उक्त छूट हेतु राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं राज्य सरकार/उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
(डा० अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1709 (1)/VII-2-13/204-उद्योग/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इरला रोड विले पारले, पं० मुंबई-56
5. निदेशक, राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- ✓ 8. निदेशक, एन० आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(किशन नाथ)
अपर सचिव।